



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 आषाढ 1938 (श10)

(सं0 पटना 550) पटना, बृहस्पतिवार, 30 जून 2016

सं० 2/ सी०-1065/2009-5693-सा0प्र0
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

15 अप्रैल 2015

श्री अविनाश कुमार (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 891/11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, मोहिउद्दीन नगर सम्प्रति जिला आपूर्ति पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम के विरुद्ध सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या 14657/06 (कुमारी आरती बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.09.2007 के आलोक में नियमानुसार आदेश पारित नहीं करने, जिन बिन्दुओं पर सुनवाई करना था उन पर सुनवाई किये बगैर पंचायत के मुखिया को मानदेय का भुगतान करने तथा सेवा विस्तार करने का आदेश देने संबंधित आरोपों के लिए जिलाधिकारी, समस्तीपुर के पत्रांक 4115 दिनांक 16.08.2010 द्वारा आरोप-पत्र प्रपत्र 'क' प्राप्त हुआ। उक्त आरोपों के संदर्भ में श्री अविनाश कुमार से विभागीय पत्रांक 1835 दिनांक 11.02.2011 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी। तत्पश्चात् स्मार पत्र संख्या 5903 दिनांक 26.05.2011, 9426 दिनांक 23.08.2011 एवं 8025 दिनांक 05.06.2012 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु स्मारित भी किया गया। श्री कुमार द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित नहीं करने पर विभागीय संकल्प ज्ञापांक 280 दिनांक 08.01.2014 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

आयुक्त के सचिव, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा के पत्रांक 1076 दिनांक 25.11.2014 द्वारा प्राप्त आयुक्त-सह-संचालन पदाधिकारी, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में आरोपित पदाधिकारी के स्पष्टीकरण को आंशिक रूप से स्वीकार योग्य प्रतिवेदित किया गया।

श्री कुमार से उपर्युक्त प्रमाणित आरोप के लिए विभागीय पत्रांक 245 दिनांक 06.01.2015 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 18(3) के संगत प्रावधानों के तहत अभ्यावेदन की मांग की गयी, जिसके आलोक में श्री अविनाश कुमार ने पत्रांक 202 दिनांक 31.01.2015 द्वारा अपना अभ्यावेदन समर्पित किया।

श्री कुमार ने अपने अभ्यावेदन में कहा है कि सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या 14657/06 में दिनांक 17.09.2007 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अनुपालन हेतु आदेश के अनुरूप विधि सम्मत् कार्यवाई करते हुए आवेदकों के बकाया भुगतान एवं सेवा विस्तार के लिए उन्होंने ज्ञापांक 1521 दिनांक 30.11.2007 द्वारा संबंधित मुखिया को निदेश दिया था तथा उसकी सूचना आवेदकों को भी दी गई। प्रपत्र 'क' की कंडिका- 02 के साथ-साथ अन्य सभी आरोपों के संबंध में इन्होंने अपना स्पष्टीकरण आयुक्त महोदय को अभ्यावेदन दिनांक 10.09.2014 द्वारा समर्पित किया, जिसमें इनका कहना है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 17.09.2007 को पारित आदेश के आलोक में आवेदकों से अभ्यावेदन प्राप्त होने पर अभिलेख एवं नियमों का अध्ययन कर नियमानुसार आवेदकों के मानदेय भुगतान एवं सेवा विस्तार का लाभ देने हेतु संबंधित मुखिया, ग्राम पंचायत- सिवैसिंगपुर को निदेश दिया गया। तदुपरांत न्यायादेश का अनुपालन प्रतिवेदन इनके द्वारा दिनांक 30.11.2007 को माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल किया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा

निर्धारित समय सीमा के अन्दर इनके द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की गयी। उक्त स्पष्टीकरण दिनांक 10.09.2014 पर जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर के द्वारा दिये गये मंतव्य पर भी इन्होंने आवेदन दिनांक 09.10.2014 के द्वारा अपना पक्ष समर्पित किया। श्री कुमार द्वारा उक्त अभ्यावेदन में पुनः उन्हीं तथ्यों का उल्लेख किया गया जो इनके पूर्व के अभ्यावेदन दिनांक 10.09.2014 में किया गया था। इसके अलावा इनके द्वारा यह भी कहा गया कि उनके आवेदन दिनांक 10.09.2014 एवं 09.10.2014 द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को सत्य मानते हुए आयुक्त महोदय द्वारा दिनांक 18.11.2014 को पारित आदेश में अक्षरशः स्वीकार किया गया। उक्त आधार पर श्री कुमार के द्वारा उन्हें दोषमुक्त करने का अनुरोध किया गया।

आरोप-पत्र, संचालन पदाधिकारी का जाँच प्रतिवेदन एवं श्री कुमार के द्वारा समर्पित अभ्यावेदन की समीक्षा के उपरान्त यह पाया गया कि श्री कुमार का यह कहना कि उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को संचालन पदाधिकारी के द्वारा सत्य माना गया है, सही नहीं है, क्योंकि संचालन पदाधिकारी के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में निष्कर्ष स्वरूप प्रतिवेदित किया गया है कि "उपरोक्त परिप्रेक्ष्य के आलोक में आरोपित पदाधिकारी का स्पष्टीकरण आंशिक रूप से स्वीकार योग्य प्रतीत होता है। सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या 14657/06 (कुमारी आरती बनाम् बिहार राज्य एवं अन्य) में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 17.09.2007 को निम्न आदेश पारित किया गया :-

"Let the petitioners submeet their separate representation (s) raising all grievances before respondent no. 12 (Block Development Officer, Mohaddi Nagar, District-Samastipur) which, if filed within a period of four weeks from today, shall be disposed of by a reasoned order and in accordance with law within a period of two months from the date of submissions of the representations."

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उपर्युक्त आदेश के आलोक में श्री कुमार के द्वारा विधिवत् अभिलेख संधारित करते हुए संबंधित पक्षों को विधिवत् सूचना देते हुए सकारण आदेश पारित करना चाहिए था, लेकिन श्री कुमार के द्वारा साक्ष्य स्वरूप समर्पित ज्ञापांक 1521 दिनांक 30.11.2007 के अवलोकन से स्पष्ट है कि श्री कुमार के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश के आलोक में Reasoned Order पारित नहीं किया गया है, बल्कि प्रासंगिक पत्र के द्वारा मुखिया, ग्राम पंचायत राज-सिवसिंगपुर को आरती कुमारी एवं जतन कुमार पासवान के मानदेय का भुगतान करने तथा सेवा विस्तार का लाभ देने का निदेश दिया गया। प्रासंगिक रिट याचिका में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन हेतु जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर के पत्र संख्या 5983 दिनांक 12.12.2008, 7134 दिनांक 30.12.2008, 143 दिनांक 10.01.2009, 757 दिनांक 23.02.2009, 1702 दिनांक 29.05.2009 एवं 1894 दिनांक 15.06.2009 के द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी, मोहिउद्दीन नगर को निदेश दिया गया था एवं स्मारित किया गया था। यदि श्री कुमार के द्वारा अभिलेख संधारित करते हुए तथा विधिवत् सुनवाई करते हुए दिनांक 30.11.2007 को आदेश पारित किया जा चुका था तो ऐसी स्थिति में उन्हें जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर के प्रासंगिक पत्रों के आलोक में जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर को अनुपालन प्रतिवेदन भेजना चाहिए था, लेकिन उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण अथवा अभ्यावेदन में कहीं भी इस तथ्य का जिक्र नहीं है अथवा इस आशय का कोई साक्ष्य संलग्न नहीं किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि श्री कुमार के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में विधिवत् सुनवाई नहीं की गयी है तथा सकारण आदेश भी पारित नहीं किया गया है, जो उनके विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों को प्रमाणित करता है।

वर्णित तथ्यों के आधार पर अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री अविनाश कुमार (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 891/11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, मोहिउद्दीन नगर सम्प्रति जिला आपूर्ति पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम के पत्रांक 202 दिनांक 31.01.2015 के द्वारा समर्पित अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए उनके विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-14 के प्रावधानों के तहत "निन्दन (आरोप वर्ष 2007-08) एवं असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक" का दण्ड निरूपित करने का निर्णय लिया गया।

अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री अविनाश कुमार (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 891/11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, मोहिउद्दीन नगर सम्प्रति जिला आपूर्ति पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-14 के प्रावधानों के तहत निम्नांकित दण्ड दिया एवं संसूचित किया जाता है :-

(क) निन्दन (आरोप वर्ष 2007-08)।

(ख) असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक।

आदेश :-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अनिल कुमार,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 550-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>